प्रधानमंत्री (श्री एच.डी. देवेगौडा) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के नेता सहित सदन के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि एक क्षण के लिये भूल जायें कि यह मिली जुली सरकार है और यह सरकार 13 दलों की मिली जुली सरकार है और इस सरकार का समर्थन एक बडी पार्टी कर रही है। मैं सदन के सत्र आरंभ होने से पांच दिन पहले पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढायें जाने के सरकार के निर्णय के पक्ष में तर्क पेश करूंगा। हमें इस मामले को राजनीति से नहीं जोडना चाहिये। सरकार के इस निर्णय के बारे में हमे व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

महोदय औचित्य के बारे में आपने विनिर्णय दे दिया है। मैं आपके निर्णय पर आपत्ति नहीं उठाना चाहता। मैं उसे सिर झुका कर स्वीकार करूंगा। जब माननीय अध्यक्ष ने उस पुणीत पीठ से अपना निर्णय दिया है तो हमें अध्यक्ष पीठ के निर्णय का आदर करना चाहिये। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपने निर्णय का अपनी सरकार के निर्णय का औचित्य सिद्ध नहीं करना चाहता। महोदय, यदि आप पिछले इतिहास को देखें और पता लगायें कि माननीय अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षपीठ से कितनी बार पिछली सरकारों के निर्णयों के बारे में विनिर्णय दिये गये है जिन सरकारों के पास दो तिहाई बहुमत था और उस समय किस प्रकार बजट सत्र से पहले प्रभावित भावों में वृद्धि की गई थी।

इस सरकार ने इतनी जल्दबाजी के साथ यह निर्णय क्यों किया या बजट सत्र के 6 दिन या एक सप्ताह पूर्व यह निर्णय क्यों किया? किसी भी निष्कर्ष पर पहुचने से पहले हमें सारी स्थिति को ध्यान में रख लेना चाहियें।

महोदय हमारे सामने समस्या वही थी जो पिछली सरकार के सामने थी। वही उसका हमारे वरिष्ठतम नेता, भूतपूर्व प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता के सामने थी।

मैं जसवन्त सिंह जी का सबसे अधिक आदर करता हूं। जब भी वह बोलते थे मैं वहां बैठकर बडे ध्यान से उनके भाषण को सुनता था। कई बार मैं कुछ शब्दों व अभिव्यक्तियों को समझ नहीं पाता था। जहां तक अंग्रेजी का संबंध है मुझे उसका अच्छा ज्ञान नहीं है परन्तु मैं उनका भाव समझ जाता था जो वे इस सदन से राष्ट्र को बताना चाहते थे।

उनके लाभ के लिये मैं उनके ही शब्द उद्धृत कर रहा हूं जो उन्होंने पिछली सरकार के सामने जब यह मामला आया था तो उस समय कहे थे। जब वित्त मंत्रालय को यह फाईल भेजी गई थी तो वित्त मंत्री ने उस पर सबसे अंत में यह विचार व्यक्त किया था कि :

> "प्रथम दृष्टया यह अनिवार्य लगता है कि पूल के घाटे को समाप्त करने के लिये पीओएल में तत्काल वृद्धि जरूरी है!"

वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने यह विचार व्यक्त किये थे। मैं यह नहीं कह रहा कि उन्होंने यह विचार वित्त मंत्रालय से लिया था ...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या यह निर्णय जसवन्त सिंह जी का है?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : जी हां।

मैं अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता का बहुत आदर करता हूं। महोदय मैं उनका सम्मान करता हूं। वित्त मंत्री ने भी टिप्पणी की है कि तेल पूल का सचंयी घाटा पिछले साल के 5700 करोड़ रु. से बढ़ कर इस साल के अंत तक 11700 करोड़ रु. हो जाने की संभावना है और इस कारण उस पूल घाटे को दूर करने के लिये तत्काल पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों मे वृद्धि करना जरूरी था। मैं कुछ शब्दों को पुनः पढ़ रहा हूं "पूल घाटे को दूर करने के लिये तत्काल"। पूल घाटा कितना था? पिछले साल के लिये यह घाटा 5700 करोड़ रु. था और 1996-97 में घाटा बढ़ कर 11700 करोड़ रु. हो जाने कर अनुमान था।" अगर ये इन मुद्दों पर कार्यवाही अलग से की जायेगी, कोई ओ.ई.बी. वित्त मंत्रालय द्वारा यथा स्वीकृत, मंजूरी हेतु प्रस्तुत है"। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने इसे मंजूरी दे दी और यह भी निर्देश दिया कि वित्त मंत्रालय, जिसके प्रमुख श्री जसवंत सिह है द्वारा की गई टिप्पणी पर कार्यवाही की जाये। मैं यहां पर राजनीति को नहीं जोडना चाहता। इस बात को भूल जाये कि यह 13 पार्टियों की सरकार और आपका भी इसे समर्थन है। मैं दिल्ली में नौकरी की खोज में नहीं आया हूं। मेरा स्वभाव पूरी तरह से अलग प्रकार का है। मेरे ऊपर तो यह थौंपा गया है। मैं आपका बहुत सममान करता हूं आप कहीं भी हो। भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। यदि भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। यदि भाग्य आपके साथ है तो आप इस पद पर बैठ सकते हैं अन्यथा कोई और बैठ सकता है। परंतु मुद्दा यह नहीं है। जब आप एक वरिष्ठ सांसद के रूप में आक्रमण करते है तो मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूं। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आप की तुलना में मैं बहुत अदना व्यक्ति हूं। तेल पूल लेखों के घाटे की दूर किया जाना था। यह आपका निर्णय था और मैने उसका पालन किया है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्रीजी को टोकना नहीं चाहता था...

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं आपको बोलने का मौका देता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम पदार्थों में जो मंहगाई बढ़ रही है, जो अभाव हो रहा है, उसमें मामला पीछे

पड़ा है। उसके खिलाफ वर्षों से हम प्रतिपक्ष के नाते चेतावनी देते रहे हैं लेकिन मैंने अपने आदेश में नही कहा कि पार्लियामेंट का सैशन बुला लीजिये। पांच दिल पहले वृद्धि का ऐलान कर दिया जाये, यह फैसला आपका फैसला है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, विपक्ष के नेता तथा श्री जसवन्त सिंह को स्वीकार कर लेना चाहिये कि उन्होंने भारी वृद्धि किये जाने की सिफारिश की थी।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मेरे से एक प्रत्यक्ष प्रश्न पूछा गया है परन्तु मैं इसका उत्तर तभी दूंगा जब आप मुझे अनुमति देंगे।

महोदय, इसमें दो बाते हैं। पहली तो फाईलों पर लिखी टिप्पणियों के बारे में है। क्या फाईलों में लिखी टिप्पणियों पर यहां चर्चा की जा सकती है। यह एक अलग मामला है।

दूसरी बात यह है कि मेरे वरिष्ठ मित्रों ने मेरे से पूछा है कि क्या मैनें अचानक इतनी अधिक मूल्य वृद्धि की कोई सिफारिश की थी। महोदय नहीं। मैंने निश्चित रूप से इस बिगडती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी के घाटा बढ़ कर ।1000 करोड़ रु. या अधिक हो जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब तो सारा भेद खुल गया है।

श्री जसवन्त सिंह : यह अनुमान है। निश्चित रूप से यह रिकार्ड पर है कि यदि सुधारात्मक कदम नहीं उठाये गये तो स्थिति परेशानी वाली हो जायेगी। परंतु वह सुधारात्मक कदम 30 प्रतिशत वृद्धि करने का है यह निश्चित रूप से हमारी टिप्पणी में नहीं है। हमने ऐसा करने के स्थान और ससंद के बजट सत्र के समय पर ऐसा करने के स्थान पर कोई न कोई विकल्प निकाला होता। मैं यह इस कारण कह रहा हूं क्योंकि यह मामला यहां पर उठाया गया है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : यह विचार 25.5.1996 को अर्थात् लगभग 20 दिन पहले व्यक्त किया गया था। मैंने पदभार 1 जून, 1996 को ग्रहण किया था और संसद में यह सिद्ध किया जाना था कि सरकार को बहुमत हासिल है अथवा नहीं। अतः मैं अगले 12 दिन तक इस फाईल को नहीं देख सका। मैं इस निर्णय का बचाव करने के लिये ही वरिष्ठ नेताओं का नाम इससे नहीं जोड रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तो वाद विवाद में जीतने के लिये इस तरह कह रहे हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : कृपया मेरी बात सुने। कुछ दिन पहले जब आप बोल रहे थे तो अन्य माननीय सदस्यों ने मेरे ऊपर इतने प्रहार किये। मैं धीरज के साथ उनकी बातें सुनता रहा। मैंने तो किसी भी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। मैं तो सारे अपमान को चुपचाप सहन कर गया था।

श्री जसवन्त सिंह जी, आपकी समिति ने संसद द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिश की थी कि रसोई गैस पर सबसिडी को धीरे कम कर दिया जाये। आप इस समिति के अध्यक्ष थे। मुद्रास्फीति के बारे में **टाइम्स आफ इंडिया** से बातचीत करते हुए आपने कहा था कि मुद्रास्फीति की दर को प्रसाशित भावों को न बढ़ा कर अप्राकृतिक ढंग से कम रखा गया है। इसके आगे आपने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में विशेष रूप से ऐसा है क्योंकि तेल पूल लेखे में 6000 करोड़ रु. का घाटा है। यह आपने संवाददाता को बताया था। ...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे पूरी तरह बेनकाब हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से ऐसा कहना जरूरी नहीं है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : महोदय, मैं सदन को और इस सदन के माध्यम से राष्ट्र को उन परिस्थितियों के बारे में बताना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप मुझे समर्थन करें। मैं पूरा दोष अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। परन्तु कम से कम इस सदन के जरिए मुझे राष्ट्र को तो बताना होगा कि यह निर्णय मैंने किन परिस्थितियों के अन्तर्गत किया है। इतनी तो मुझे आजादी है।

महोदय, 17 जून को एक रिफाईनरी ने कहा कि इंडियन आयल कारपोरेशन को कच्चे तेल की सप्लाई के लिये एफ.ओ.बी. अदायगी के रूप में 49 करोड़ रु. की अदायगी स्थगित कर दी गई है। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि अन्य सप्लायर्स को अदायगियों में विलम्ब के कारण प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुचंता है। यदि ओ सी सी के द्वारा इस तरह की आगे छटनी की जाये तो उससे सीआईएल को गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिनके कारण रिफाइनरी का संचालन रूक भी सकता है एक रिफाइनरी के चैयरमैंन तथा प्रबंध निदेशक ने पेट्रोलियम मंत्रालय कि सचिव को ऐसा चेतावनी देन वाला एक पत्र भी लिखा। तेल शोधक अनेक कारखानों, और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच पत्रों का आदान प्रदान हुआ। मैं केवल एक मामले का उदाहरण देता हूं क्योंकि मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इसमें कहा गया है:

> "हमे डर है कि यदि यह स्थिति जारी रही तो इंडियन आल्य कारपोरेशन को आयात के लिये विदेशी मुद्रा अदायगियों ओर अपने ऋणों की अदायगी करने में भी दिक्कतें आएगी जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी साख पर प्रतिकुल असर पडेगा।"

उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय से शीघ्र निर्णय के लिये लगातार जोर डाला। कुछ लोगों का कहना है कि मैंने सब से बड़ी गलती की है। अभी भी मार्च 1997 तक घाटा 4700 करोड़ रु. से 5000 करोड़ रु. के बीच होगा। यह अनुमानित आंकडे हैं।

मैं सदन का ध्यान पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई पिछली मूल्य वृद्धियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इस संबंध में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई अब तक की वृद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। वर्ष 1979 में इसी सदन में 28 फरवरी को बजट पेश कर दिये जाने के बाद । मार्च, 1979 को श्री मोरारजी देसाई उस समय प्रधान मंत्री थे, एच.एस.डी. के मूल्य में 8.5 प्रतिशत, मिट्टी के तेल के मूल्य में 8.3 प्रतिशत तथा रसोई गैस के मूल्य में 9.2 प्रतिशत वृद्धि की गई थी।

जब स्वर्गीय श्री चरण सिंह प्रधानमंत्री पद पर असीन हुए तो 17 अगस्त, 1979 को इस सदन में बजट पारित किये जाने के 6 महीने बाद रसोई गैस के मूल्य में 20.4 प्रतिशत वृद्धि की गई।

जब श्रीमती गांधी प्रधान मंत्री थी। 13 जनवरी, 1981 को, बजट 28 फरवरी, 1981 को पेश दिया गया था-रसोई गैस के मूल्य बजट से डेढ़ महीना पहले 17 प्रतिशत बढाये गये और एच.एस.डी. के मूल्य 18.9 प्रतिशत बढ़ाये गये। छह महीने के भीतर अर्थात 11 जुलाई, 1981 दो साल के मध्य में, एच.एस.डी. के मूल्य फिर से 13.7 प्रतिशत बढ़ा दिये गये। यदि आप दोनों वृद्धियों अर्थात 18.9 प्रतिशत और 13. 7 प्रतिशत को जोड़े तो एच.एस.डी. में ही कुल वृद्धि 32 प्रतिशत बैठ जाती है। रसोई गैस का मूल्य 13 जनवरी, 1981 को 17 प्रतिशत बढाया गया और । जुलाई, 1981 को फिर से 14.5 प्रतिशत बढ़ाया गया था। यह कुल मूल्य वृद्धि रसोई गैस के मामले में 31.5 प्रतिशत बैठती है। मिट्टी के तेल के मूल्य 6 महीनों में दो किश्तों में 18.5 प्रतिशत बढ़ा दिये गये थे।

श्री राजीव गांधी के शासन काल के दौरान 1 फरवरी, 1986 को - बजट 28 फरवरी 1986 को पेश किया गया था - रसोई गैस के मूल्य में 23.1 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई जिसमें बाद में कुछ कटौती कर दी गई थी...(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : कटौती कितनी थी?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : यह 9 प्रतिशत थी।

श्री संतोष मोहन देव : उन्होंने मूल्य बढाया और बाद में घटा दिया।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं इस ओर भी आ रहा हूं। इसी कारण मैंने कहा है कि हम पार्टी की बातों को भूल जायें। हमें देखना है कि हम वर्तमान संकट को किस हद तक दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं। बहुत सी अन्य समस्याएं हैं और हमें उनके बारे में मिल जुल कर सोचना है। वर्ष 1991 में एच.एस.डी. के भाव नहीं बढाये गये। 25 जुलाई, 1991 को रसोई गैस के भाव 20 प्रतिशत बढाये गये थे; 16 सितम्बर, 1992 को इसमें 24.1 प्रतिशत वृद्धि की गई और 12 जनवरी, 1994 को इसमें 20.6 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई। तीन सालों में रसोई गैस के भावों में कुछ मिलाकर 64.6 प्रतिशत वृद्धि की गई है। बाद में भावों में 6.9 प्रतिशत कटौती कर दी गई। इसका अर्थ है कि तीन साल में अकेले रसोई गैस 58 प्रतिशत वृद्धि की गई है। आप सब कह रहे थे कि प्रधान मंत्री को आम आदमी की समस्याओं की कोई जानकारी नहीं हैं। मैं इस सारी आलोचना को सुनने को तैयार हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सदन में इस ओर बैठे लोग वास्तविक भूमि पुत्र हैं।

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, मैने आपको बताया है कि हमें यह निर्णय किन परिस्थितियों में करना पड़ा हमारी मांग - आपको भी वह बताई गई और मुझे भी बताई गई.- 1994-95 में 655 लाख टन की और यह बढ़कर 725 लाख टन हो गई है। चालू वर्ष के दौरान इसके बढ़कर 785 लाख टन हो जाने की संभावना है।

जैसा कि मैने कुछ समय पहले आपको बताया इस मूल्य वृद्धि के बाद भी 31 मार्च, 1997 को 4700 करोड़ रु. से 6000 करोड़ रु. का घाटा शेष रह जायेगा।

हम कितनी सबसिडी दे रहे हैं। हम मिट्टी के तेल में 4870 रु. की सबसिडी दे रहे है। हम प्रति लीटर 4.17 रु. की सबसिडी दे रहे हैं।

ऐसा कहा गया कि यह मध्यरात्रि को किया गया निर्णय है। यह मध्य रात्रि निर्णय नहीं है। हर बार जब प्रशसित मूल्य बढ़ाया जाना होता है, तो वह निर्णय 10.30 या 11.00 बजे के लगभग जब तेल पम्पों और पेट्रोल पम्पों के हिसाब किताब पूरे हो जाते हैं समय से लागू किया जाता है।

श्री हरिन पाठक : उनमें वृद्धि करनी होती है।

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं इसे मानता हूं। मेरा इस पर कोई विवाद नहीं है। मैं मानता हूं कि यह सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने मध्य रात्रि निर्णय किया है। यह विभाग का निर्णय है। जी हां। इसे अगले दिन से लागू किया जाना चाहिये। इसी कारण वे अपने लेखे बंद करने के बाद सम्बद्ध डीलरों को सूचित करेंगे।

आज भी हम रसोई गैस के सिलेन्डर पर 62.50 रु. की सबसिडी दे रहे है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अगर 62 रु. सबसिडी है तो एल.पी.जी पर सबसिडी को बंद कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा : बंद कीजिए का अर्थ है पूरी तरह से खत्म करना। यदि आप इसे पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं तो जब

इस सरकार के गिरने के बाद आप सत्तारूढ़ हों तब आप ऐसा कर सकते हैं।...(व्यवधान)

यदि हम 250 रु. से कम मासिक आय वाले रसोई गैस प्रयोक्ताओं को देखे तो वह गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यह 3.8 प्रतिशत है।

750 रु. से 1500 रु. की मासिक आय वाले लोगों की प्रतिशतता 25.9 है और 1500 रु. से 2500 रु. की आय वाले लोगों की प्रतिशतता 29.1 है तथा 4000 रु. से ऊपर वाले 17.7 प्रतिशत है।

मैं यह आंकडे सदन को बता रही हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह सर्वेक्षण किस ने किया है?

श्री एच.डी. देवेगौडा : यह विभाग के द्वारा किया गया है। किसी समाचार एजेंन्सी ने नहीं किया है। भारत में रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि किये जाने के बाद भी इसके भाव 8.46 रु. प्रति किलो है जबकि पडोसी देश मलेशिया में भाव 16.12 रु. हैं बांग्लादेश में वह हम से अमीर हैं - भाव 13.50 रु. है, म्यांमार में 22.37 रु. है और श्रीलंका के भाव 13.4 रु. एवं थाईलैण्ड में रसोई गैस का भाव 15.4 रु. प्रति किलो है।

एच.एस.डी. के बारे में सड़क परिवहन में जिन्सों की ढुलाई पर कुछ असर जरूर पडेगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। सारे देश में सड़क परिवहन विभागों की कुल खपत 61.8 प्रतिशत है, रेलवे के लिये यह 4.3 प्रतिशत है; नौवहन के मामले में यह 0.4 प्रतिशत होता था कृषि क्षेत्र में इसकी खपत 16.3 प्रतिशत है। औद्योगिक क्षेत्र में खपत की प्रतिशतता 17.2 प्रतिशत है। एच.एस.डी. की क्षेत्रवार खपत इस तरह है।

जहां तक वाहनों की संख्या की बात है डीजल कारों की संख्या 310412 है, जीपों की संख्या 598191 है और वाणिज्यक वाहनों की सख्या 21,27,504 है

मैं अब मोटर स्पिरिट की खपत के आकंडे बताता हूं। देश में कुल 13676000 कारें हैं। कुल खपत 19810973 मीटरी टन है। मैंने क्षेत्रवार खपत तथा साथ में डीजल से चलने वाले वाहनों, कारों की संख्या तथा इस तरह की बातें बताई हैं। कुल खपत लगभग 1,98,10,973 मीटरी टन हैं।

श्री नीतीश कुमार : ट्रैक्टरों की क्या स्थिति है...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैंने आपको बताया कि कितने किसान इन का उपयोग कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब भी किसी वस्तु के भावों में वृद्धि की जानी होती है तो उसका भार कुछ वर्गों पर पड़ना स्वाभाविक है। मैं इस पर विवाद नहीं पैदा कर रहा। परंतु इसके साथ ही हम अन्य लोगों के बारे में भी सोचें। नीतीश जी। मैं सोचता था कि आप कृषक वर्ग से हैं...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने इसे छोड़ दिया है। वह अब मन्दिर बनाने के काम में लग गये हैं...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं उनका बहुत आदर करता हूं। श्री नीतीश कुमार जी मैंने आपका भाषण सुना है हालांकि मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था। मैं आपके भाषण को पूरी तरह से समझ नहीं सका क्योंकि आप हिन्दी में बोले थे। परंतु मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आपने इस सरकार के द्वारा दी गई उर्वरक सब्सीडी के बारे में कम से कम एक शब्द भी नहीं कहा है।

श्री नीतीश कुमार : मैं इसकी सराहना करता हूं। परंतु श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने इसकी पूरी जानकारी नहीं दी है।

श्री एच.डी. देवेगौडा : यदि आपने उल्लेख किया है तो आपका धन्यवाद मेरे विचार से भारत को आर्थिक दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग ग्रामीण भारत है और दूसरा भाग शहरी भारत है। यह न समझें कि मैं शहरी लोगों के प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैया रखता हूं। अथवा ग्रामीण लोगों के प्रति नरम हूं। इस बात को भूल जायें। मैं आपको केवल आंकड़े बता रहा हूं। मुम्बई, कलकत्ता, और मद्रास में ही रेलवे को 220 करोड़ रु. का घाटा सहन करना पड़ता है जिसके लिये हम सब्सीडी दे रहे हैं। यह उपनगरीय गाड़ियों के लिए है।

श्री नीतीश कुमार जी पोस्ट-कार्डों, रजिस्ट्रेशन फीस तथा अन्तर्देशीय पत्रों की बिक्री पर अकेले संचार विभाग में हम 600 करोड़ रु. की सब्सीडी दे रहे हैं।

इस सब का लाभ किसे मिल रहा है? यह लाभ जनता को मिल रहा है। बिहार में नरसंहार हुआ। मुझे वह खबर शनिवार को सुबह 7.30 बजे मिली। मैंने गृह मंत्री को कहा, "मैं आज दोपहर बाद उस स्थान पर जाना चाहता हूं जहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव से सम्पर्क स्थापित किया और उन्होंने दो घंटों में जानकारी प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि यद्यपि आप भारतीय वायुसेना के विमान से पटना तक जा सकते हैं। परंतु आप उस गांव तक हैलिकाप्टर के जरिए भी नहीं पहुंच सकते। हम उस गांव से 2 मील की दूरी पर हैलीपैड की व्यवस्था कर सकते हैं। आपको 2 मील पैदल चलना पड़ेगा।" यह भारत की असली तस्वीर है। आप उसी राज्य से हैं। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। 27 तारीख को क्या हुआ? मैं उस स्थान पर उसी दिन जाना चाहता था, क्योंकि वह छुट्टी का दिन था और सदन की बैठक नहीं थी। गृह सचिव ने मुझे बताया "आपको दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और हम आपको आज वहां आने की सलाह नहीं देते।" जैसा कि मैंने आपको बताया है आर्थिक दृष्टि से हम भारत को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग ग्रामीण भारत है और भाग शहरी भारत है। हम समाज के विभिन्न वर्गों को कितनी सब्सीडी दे रहे हैं? मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। परंतु आपको उन लोगों के बारे में भी विचार करना चाहिये जिनकी कोई आवाज

नहीं है। यह सदन उन लोगों के लिए है जिनकी कोई आवाज नहीं है। मैंने जो निर्णय किया है उसे समाज के बहुत से सम्पन्न वर्गों द्वारा पसन्द नहीं किया जायेगा। मैं जानता हूं कि वे जनमत बनाने वाले हैं। वह इस सरकार के विरुद्ध अपना मत बना सकते हैं। परंतु मैं आपको साफतौर पर बताना चाहता हूं कि जब तक मैं यहां पर हूं मैं ग्रामीण जनता के हित के निर्णय करूंगा। मैं यह कहने को तैयार हूं। मैं इस पद से नहीं डरता। जब तक मैं यहां पर हूं मैं अपनी निर्णायकों के हित के फैसले करूंगा। उन लोगों के हित में सोचूंगा। जिनकी इन 48 सालों में उपेक्षा की गई है। निश्चित रूप से उन्हें अपना हक मिलना ही चाहिये। बहुत हो चुका।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : प्रधान मंत्री जी डीजल, पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाने का असर भी तो उसी वर्ग पर पड़ने जा रहा है जिस वर्ग की बात आप कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री महोदय, जिन पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ा रहे हैं उनका प्रतिकूल असर भी तो गरीब लोगों पर ही पड़ रहा है जिनकी वकालत प्रधान मंत्री महोदय कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी) : माननीय प्रधान मंत्री महोदय, बिहार में अगर सड़कें नहीं हैं, तो उसका दोषी कौन है? बिहार में अगर विकास नहीं हो पा रहा है, तो उसका दोषी कौन है? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री एस.पी. जायसवाल : प्रधान मंत्री महोदय, आप किसानों के नेता हैं। आप दो किलोमीटर पैदल चल सकते हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, मैं यह कहता हूं कि विपक्ष को सरकार पर आक्रमण करने का अधिकार है। विपक्ष ने जितनी भी कठोर भाषा का उपयोग किया मैंने अपने होंठ नहीं खोले। कुछ समय के लिये मेरी बात सुने। हम सभी मानव हैं। हम यहां पर उन लोगों की चिंता के लिये भी भेजे गये हैं। यह देवेगौड़ा का एकाधिकार नहीं है। कृपया मुझे बोल लेने दें।

यदि मैं बंगलौर का उद्धरण दूं तो आप कहेंगे कि मैं हमेशा बंगलौर की बात करता हूं। हम दिल्ली में इस पर कितनी सब्सीडी दे रहे हैं? 50 करोड़ रु. की सब्सीडी दी जा रही है। दिल्ली दुग्ध योजना के लिये लगभग 50 करोड़ की सब्सीडी दी जा रही है। दिल्ली में बिजली की सप्लाई के लिये 40 प्रतिशत सब्सीडी दी जाती है। दिल्ली में परिवहन पर 120 करोड़ रु. की सब्सीडी दी जा रही है।

इसको देखते हुए हमें मिल जुल कर उन लोगों के बारे में विचार करना चाहिये जिनकी मूल जरूरतें हैं।

महोदय, मैंने इस मूल्य वृद्धि से पहले मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। मैं उनके विचार सुनना चाहता था। मैंने अपनी पृष्ठ भूमि के साथ स्वयं अपने हाथों से उस बैठक की कार्य सूची तैयार की थी। मैंने सम्मेलन से 12 दिन पहले मुख्य मंत्रियों को पत्र लिख कर उनसे कहा कि वे अपने विचार बनाकर आएं। मैं उनको सुनना चाहता था। हमने दो दिन तक बैठक की। आमतौर पर कोई भी प्रधान मंत्री 2 दिन तक सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। वह सम्मेलन का उद्घाटन करेगा और चला जायेगा। मैं यह इस कारण कह रहा हूं क्योंकि मैं लगभग पांच वर्ष के लिये कर्नाटक का कृषि मंत्री था और मैंने कृषि मंत्रियों के तीन सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं और बाद में श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे। वे प्रायः उद्घाटन करते थे और चले जाते थे। मैं दो दिनों के लिये 16 घंटे के लिये वहां बैठा रहा क्योंकि मैं हर मुख्य मंत्री के विचार सुनना चाहता था। हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से सात क्षेत्रों को अर्थात संचार, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक वितरण तथा मध्यान्तर भोजन को प्राथमिकता देने का फैसला किया।

महोदय, आजादी के 48 वर्ष बाद भी उत्तर प्रदेश में लगभग 63000 गांवों में से उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने यह आकड़े दिये हैं और उसी के आधार पर मैं यह आंकड़े बता रहा हूं, यह मेरे स्वयं के आंकड़े नहीं हैं-35000 गांवों में स्कूलों की इमारतें नहीं है। इस राज्य ने देश को 6 प्रधान मंत्री दिये हैं।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सब इन्होंने चौपट कर दिया ...(व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी मिश्र : आप जवाब दें, आपने क्या किया है? ...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : इसके लिये आप जिम्मेदार हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनायें।

(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, 1.18 लाख गांवों में कोई सड़क नहीं है। यह आंकड़े राज्य सरकार ने दिये हैं।...**(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : हर कोई जानता है कि 48 साल व्यतीत हो चुके हैं। परंतु इसके लिये जिम्मेदार कौन हैं?...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के सदस्य मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या किया?

[अनुवाद]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : क्या आपने डीजल के भाव बढ़ाने का निर्णय करके ग्रामीण लोगों की सहायता की है? ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका। कृपया।

श्री एच.डी. देवेगौडा : कौन जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार नहीं है मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे केवल इस बात की चिंता है कि हम उन लोगों की कितनी सहायता कर सकते हैं। मुझे केवल यही चिंता है। इसी कारण मैंने मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। मुझे इस सदन को यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि लगभग सभी मुख्य मंत्रियों ने, भाजपा के मुख्य मंत्रियों सहित राजनैतिक विचारों को भुला कर सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करने में सहयोग किया कि उन बातों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाये जो मैंने अभी बताया है। यह एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिये। सन् 2000 तक जो भी कमी है हमें चार साल में पूरी करनी है। यह हमारा निर्णय है। हम सर्वसम्मति से सहमत हुए हैं और मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि हम इन क्षेत्रों हेतु आवंटन में हर साल 15 प्रतिशत वृद्धि करना चाहते हैं। केन्द्रीय सरकार के आवंटन में हर साल 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी यह राशि राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जायेगी। चाहे राज्य सरकारों का शासन भाजपा के हाथों में हो या कांग्रेस के या द्रमुक पार्टी के हाथों में हो। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं होगी। मैं यह देखना चाहता हूं कि कम से कम अगले चार सालों में 21वीं शताब्दी के आरंभ होने से पहले इन क्षेत्रों में आम आदमी की मौलिक जरूरतों को पूरा किया जाये। यह हमारी चिंता है।

यदि हम इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिये संसाधन कहां से लायेंगे। यह प्रश्न हमारे विपक्ष के नेता तथा भूतपूर्व प्रधान ने पूछा था। उन्होंने पूछा "आपके मन में 10। योजनाएं हो सकती हैं किन्तु आप संसाधन कहां से लायेंगे?" मैं आम न्यूनतम कार्यक्रम का उल्लेख करके बता रहा हूं कि हम संसाधन कैसे जुटायेंगे। जब तक हम उन लोगों को नहीं छुएंगे जिनके पास फाल्तू पैसा है, यह संभव नहीं होगा। क्या वे रसोई गैस के सिलेन्डर के लिये 26 रु. और अदा वहीं कर सकते हैं?

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पूछें।

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं हरेक से पूछूंगा। इसीलिये मैंने कहा कि हमें राजनीति को इसमें नहीं लाना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे विचार तो सिद्धांतों पर आधारित हैं। आपके नहीं हैं।

श्री हरिन पाठक : क्या सिद्धांत? इस तरफ से उस तरफ जाना।

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं इन उत्पादों के प्रयोक्ताओं से अपील करता हूं कि वे भी तेल पूल लेखे में वर्तमान घाटे को पूरा करने में सरकार से सहयोग करें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री एच.डी. देवेगौडा : आप जो करना चाहते हैं करें। वह आपका अधिकार है। मैं उसे कैसे रोक सकता हूं। आपको सदन के भीतर व बाहर मेरा विरोध करने का पूरा अधिकार है। कोई भी उसे नहीं रोक सकता। आपको जनता को यह बताने का पूरा अधिकार है कि यह ऐसा व्यक्ति है जो रसोई गैस प्रयोक्ताओं के प्रति विद्वेष रखता है। आप जायें और जनता को यह बतायें। मैं आपको सदन के बाहर और सदन के भीतर अपना विरोध करने से नहीं रोकना चाहता। परंतु इस सदन के जरिए मैं सभी उपभोक्ताओं से अपने भाईयों और बहिनों से यह अपील करता हूं कि इस वर्तमान संकट से निपटने के लिये इस सरकार के साथ सहयोग करें। मैं केवल इतनी अपील ही कर सकता हूं। मेरा मुख्य उत्तरदायित्व देश के सामने इस समस्या से निपटना है।

श्री हरिन पाठक : यह कटौती की स्लिप है।

श्री एच.डी. देवेगौडा : हम डीजल में 15 प्रतिशत कटौती कर चुके हैं। किसी और कटौती का तो प्रश्न ही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आजकल लकड़ी के भाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा : आपके पास सरकार का विरोध करने के लिय बहुत समय है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं?

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं जनता के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि हमने जो अभी निर्णय किया है उसके लिये सरकार से सहयोग करें।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 16 जुलाई, 1996 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 6.49 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 16 जुलाई, 1996/25 आषाढ़, 1918 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।